आयकर आयुक्त, हरियाणा बनाम मैसर्स जैन स्टील रोलिंग

मिल्स, हिसार (जी. सी. मित्तल, जे.)

जी. सी. मितल और एस. एस. सोढ़ी, न्यायमूर्ति के समक्ष

आयकर आयुक्त, हरियाणा-याचिकाकर्ता।

बनाम

एम/एस जैन स्टील रोलिंग मिल्स, हिसार-प्रतिवादी।

1980 का इनकम टैक्स केस नंबर 38

15 नवंबर 1988.

आयकर अधिनियम (1961 का XLIII)— धारा. 256(2)-नाबालिगों को साझेदारी के लाभों में प्रवेश दिया गया-नाबालिगों के संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज नहीं-पंजीकरण के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया-केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र के निर्देशों के अनुसार अभिभावक को कोई अवसर नहीं दिया गया-ऐसा परिपत्र-क्या विभाग पर बाध्यकारी है- क्या आयकर अधिकारी पंजीकरण से इंकार कर सकता है।

माना गया कि इस तरह के परिपत्र विभाग पर बाध्यकारी हैं और एक बार ऐसा होने पर, परिपत्र पर ध्यान दिया जाना चाहिए और अभिभावकों को नाबालिगों की ओर से साझेदारी विलेख पर हस्ताक्षर करने का अवसर दिया जाना चाहिए। चूंकि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, इसलिए आयकर अधिकारी पंजीकरण से इनकार नहीं कर सका।

(पैरा 4).

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक भान के साथ वकील अजय मित्तल ।

उत्तरदाताओं के लिए कोई नहीं।

आदेश

गोकल चंद मितल, जे.

(1) राजस्व निगम चाहता है कि अदालतें निम्नलिखित प्रश्न पर मामले के बयान के लिए परमादेश जारी करें:

> "क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, न्यायाधिकरण यह मानने में सही था कि पंजीकरण के लाभों को कमी के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
>
> **एल.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1989)2**
>
> अभिभावकों के हस्ताक्षर, जब तक कि ऐसे अभिभावकों ने दस्तावेज़ों को सत्यापित करने या हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं किया हो

मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:

(2) कुछ नाबालिगों को साझेदारी के लाभों में प्रवेश दिया गया था, लेकिन नाबालिगों के अभिभावकों द्वारा साझेदारी विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। इस आधार पर साझेदारी के पंजीकरण के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, ट्रिब्यूनल में अपील पर पंजीकरण का आदेश इस तर्क पर दिया गया था कि परिपत्र सीबीडीटी संख्या 210/13/74/ आईटीए (II) दिनांक 19 मार्च, 1976 द्वारा, केंद्रीय बोर्ड ने निर्देश जारी किए थे कि निर्धारिती की आवश्यकता नहीं है। अभिभावक के हस्ताक्षर की कमी के कारण पंजीकरण से इनकार कर दिया गया जब तक कि ऐसे अभिभावक ने दस्तावेज़ को सत्यापित करने या हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं किया, यदि ऐसा करना आवश्यक हो। चूँकि अभिभावक को अवसर नहीं दिया गया था इसलिए पंजीकरण का आदेश दिया गया।

(3) हमारे समक्ष राजस्व की ओर से अतिरिक्त आयकर आयुक्त बनाम उत्तम कुमार प्रमोद कुमार(1) (1) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के आधार पर परमादेश जारी करने का तर्क उठाया गया है, जबकि वकील के लिए निर्धारिती ने परिपत्र पर

---

(1) 115 आई.टी.आर. 796.

दृढ़ता से भरोसा किया है, जो के.पी. वर्गीस बनाम आयकर अधिकारी एमाकुलम(2), एलरमैन लाइन्स लिमिटेड बनाम आयुक्त आयकर, पश्चिम बंगाल(3) में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मद्देनजर राजस्व पर बाध्यकारी है। और कृषि आयकर आयुक्त केरल बनाम पेरुनाड प्लांटेशन लिमिटेड(4) , जिसमें यह माना गया है कि ऐसे परिपत्र विभाग पर बाध्यकारी हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि उत्तम कुमार के मामले (सुप्रा) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से आंध्र प्रदेश और कलकत्ता उच्च न्यायालयों ने श्रीनिवास स्टेनलेस स्टील और मोल्डिंग वर्क्स बनाम आयकर आयुक्त(5) और आय आयुक्त के मामले में असहमति जताई थी। आयकर आयुक्त बनाम एसोसिएट औद्योगिक वितरक(6).

(4) हमने ऊपर उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के तीन निर्णयों का अध्ययन किया है और पाया है कि यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि इस तरह के परिपत्र विभाग पर बाध्यकारी हैं और एक बार ऐसा हो जाने पर, उपर्युक्त परिपत्र पर ध्यान दिया जाना चाहिए था और अभिभावकों को नाबालिगों की ओर से साझेदारी विलेख पर हस्ताक्षर करने का अवसर दिया जाना चाहिए था चूंकि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और आयकर अधिकारी पंजीकरण से इनकार नहीं कर सके

(5) इसके परिणामस्वरूप, उनकी राय की परवाह करते हुए कोई प्रश्न नहीं उठता है और राजस्व का आवेदन लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

आर.सी.जी.

---

(2) 131 आई.टी.आर. 597.

(3) 82 आई.टी.आर. 913.

(4) 56 आई.टी.आर. 193.

(5) (1987) 167 आई.टी.आर. 1

(6) (1982) 138 आई.टी.आर. 304.

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रिंस कुमार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी